भारत सरकार

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

पंजाब में खाद्यान्न खरीद सुधारों पर केंद्रित, तीसरी राज्य स्तरीय कार्यशाला चंडीगढ़ में आयोजित

केंद्र सरकार ने पंजाब को 18 प्रमुख खाद्यान्न खरीद राज्यों में शामिल किया

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़ में खाद्यान्न खरीद सुधारों पर कार्यशाला का आयोजन किया

चंडीगढ़: 18 अगस्त, 2025

खाद्यान्न खरीद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को मजबूत करने की चल रही राष्ट्रीय पहल के तहत, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आज 18 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब के लिए तीसरी राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, **श्री संजीव चोपड़ा** और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, श्री के.ए.पी. सिन्हा ने संयुक्त सचिव (नीति एवं खाद्य निगम), विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और पंजाब सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव की उपस्थिति में किया।

इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (PUNSUP), पंजाब अनाज खरीद निगम (PUNGRAIN), राज्य भंडारण निगम (SWC) और पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (MARKFED) के प्रबंध निदेशकों सहित पंजाब की विभिन्न खरीद एजेंसियों के 125 राज्य और जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में क्षमता निर्माण, ज्ञान साझाकरण और खरीद नीतियों एवं डिजिटल सुधारों से व्यावहारिक परिचय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यशाला के दौरान, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, श्री संजीव चोपड़ा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि खाद्यान्न खरीद प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को मज़बूत करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, राज्यों के जिला-स्तरीय अधिकारियों के लिए ऐसी कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अधिकारियों को खरीद सुधारों से परिचित कराना और विभिन्न खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग पोर्टलों पर डेटा का शीघ्र और सटीक अद्यतन सुनिश्चित करना है, जिसमें लागत पत्रक तैयार करना, मार्ग अनुकूलन और सब्सिडी बिल प्रसंस्करण से संबंधित डेटा शामिल हैं।

यह कार्यशाला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 18 प्रमुख खाद्यान्न खरीद राज्यों के लिए शुरू की गई खरीद सुधारों पर राज्य-स्तरीय कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रमुख नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन में सुधार करना और डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे कि खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल (पीसीएसएपी), बिना पॉलिश किए चावल का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी), केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), एग्री-स्टैक, 10% टूटे चावल तंत्र, खरीद और भंडारण नीति के लिए रूट अनुकूलन और स्कैन मॉड्यूल को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करना है।

****

पीआईबी चंडीगढ़: रूस